

cooperatives for construction of new houses or for improvement of existing ones, to the extent of 80% of the cost of a house, subject to a maximum of Rs. 3,000. Loans are not to be granted to persons who intend to construct houses likely to cost more than Rs. 5,000 per house. The loans with interest are recoverable in easy instalments spread over a period of 20 years. As security for the loan, the borrowers are required to mortgage the land and the house or to give some other form of security acceptable to the State Government. The loan is disbursed in instalments related to the stage of construction. The State Governments are competent to frame detailed rules for implementation of the Scheme.

The Scheme also envisages:—

- (i) 100% Central grant to State Governments for provision of house-sites to landless agricultural workers and laying of streets and drains in the selected villages; and
- (ii) technical assistance and guidance to villagers and local authorities in the preparation of layout plans, designs of houses and actual construction of houses, through State Rural Housing Cells. 50% of the cost of pay and allowances of the staff of the Cells is met from Central grants.

(d) By the State Government;

(e) The Village Housing Projects Scheme is a State Plan Scheme. The State Governments are competent to frame detailed rules for implementation of the Scheme. They are also responsible for the repayment of the Central loans. The Scheme being in the State Sector, the Central Government are not in a position to impose any compulsion on the States to ensure that all the Central assistance allocated to the latter under the Scheme is utilised for the purposes of the Scheme.

मध्य प्रदेश में निर्माण प्रयोजनों हेतु सहायता

4540. श्री गं० च० दीक्षित : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि

में तथा 1967-68 और 1968-69 में अब तक (1) राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना (2) गन्दी बस्ती सफाई योजना (3) चाय बागान मजदूरों संबंधी मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत क्रमशः कितनी धन राशि मंजूर की गई;

(ख) उक्त योजनाओं पर वास्तव में कितनी धन राशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त योजनाओं में से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कितने मकानों तथा फ्लैटों का निर्माण हो जाना चाहिए था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) वांछित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-2708/68.]

तीन पंचवर्षीय योजनाओं में मध्य प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता

4541. श्री गं० च० दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में क्रमशः कितनी वित्तीय सहायता दी गई और उनके द्वारा प्रयोग न किये जाने के कारण कितनी धनराशि लौटा दी गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों में अधिक धनराशि नियत किये जाने के लिए अनुरोध किया था, और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या LT 2709/68] दी गयी सहायता का कोई